हिमाचल का पहला ऑनलाइन साप्ताहिक समाचार पत्र

आप का सामना

हक़ीक़त से

हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब,चंडीगढ़,दिल्ली, में प्रसारित

पोस्टल रजि.नंबर एचपी/33/ एसएमएल (31 दिसंबर 2024 तक मान्य)

वर्ष- 14 अंक-21 शिमला शुक्रवार,08 l 14 ekp 2024 आरएनआई एचपीएचआईएन@2010@41180 कुल पृष्ठ-6 मूल्य- 5 रू०

18 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को 1500 रुपये मासिक इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि की घोषणा

vkdlk f'keykA मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश की 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख–सम्मान निधि योजना के तहत 1500 रुपये मासिक प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस योजना को लागू कर प्रदेश सरकार ने अपनी पांचवीं चुनावी गारंटी पूरी की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में अनेक नवोन्मेषी पहल और योजनाएं लागू की जा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने इस योजना का पहला चरण 1 फरवरी, 2024 से शुरू किया था, जिसके तहत जिला लाहौल–स्पीति की महिलाओं व प्रदेश की 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 800 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक व्यय होगा और लगभग पांच लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख–सम्मान निधि योजना के तहत सरकार शीघ्र ही फार्म भरने की प्रक्रिया शुरू करेगी ताकि वे इस योजना का जल्द लाभ उठा सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सत्ता सम्भालते ही 1.36 लाख सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ देकर अपनी पहली चुनावी गारंटी पूरी की। इससे सेवानिवृत्ति के उपरान्त सरकारी कर्मचारियों का सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित हुआ है। प्रदेश सरकार ने बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्टार्ट–अप योजना आरम्भ की है। सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम शुरू करने की गारंटी पूरी करने के साथ–साथ गाय व भैंस के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य में देशभर में ऐतिहासिक वृद्धि की है और प्रा.तिक खेती को बढ़ावा देने के लिए गेहूं और मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने आपदा के कारण उपजी विभिन्न चुनौतियों का .ढ़ता से सामना किया और राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए निरन्तर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सभी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सु.ढ़ करने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। सरकार आय के अतिरिक्त संसाधन जुटाने तथा युवाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के साधन सृजित करने के लिए निरन्तर प्रयास कर रही है।

e[;ea=h us dkxMk ftyk dks nh 784 djkM #i;s dh 33 fodkl ifj;ktukvka dh lkxkr

vkdlk ngjk@uxjkVk cxokA मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को कांगड़ा जिले के अपने दौरे में देहरा और नगरोटा बगवां विधानसभा क्षेत्र में 784 करोड़ रुपये की 33 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए।

मुख्यमंत्री ने देहरा विधानसभा क्षेत्र में 356.02 करोड़ रुपये की 3 परियोजनाओं की आधारशिलाएं रखीं। उन्होंने देहरा के वनखंडी में 350 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले वन्य प्राणी उद्यान की आधारशिला रखी।

उन्होंने देहरा विस में 6.02 करोड़ रुपये की दो सड़कों नैहरन पुखर से बाड़ा वाया भरूण तथा चिंतपुरनी से बरवाड़ा के कार्य का शिलान्यास किया।

इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने नगरोटा बगवां के गांधी मैदान में नगरोटा बगवां तथा पालमपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए 427 करोड़ रुपये की 30 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए।

उन्होंने राजीव गांधी राजकीय इंजी. नियरिंग कॉलेज नगरोटा बगवां के 6. 50 करोड़ रुपये से निर्मित पुस्तकालय तथा कंप्यूटर सेंटर का उदघाटन किया। इसके अलावा उन्होंने 3.80 करोड़ रुपये की लागत के राजकीय फार्मा कॉलेज में बने 100 बच्चों की क्षमता के छात्र छात्रावास का लोकार्पण तथा 41.47 करोड़ रुपये से बने 200 बिस्तरों के श्री जी.एस. बाली मातृ शिशु अस्पताल टांडा का उद्घाटन किया।

मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी इजीनियरिंग कॉलेज में 6.80 करोड़ रुपये से बने 33 केवी सब स्टेशन का लोकार्पण भी किया। उन्होंने 22.56 लाख रुपये से बने विद्युत बोर्ड के जेई कार्यालय एवं शिकायत कक्ष का लोकार्पण किया। इसके अतिरिक्त 2.67 करोड़ रुपये से जल शक्ति विभाग की उठाऊ पेयजल योजना घीणा–मोरठ–जसाई व बालूग्लोआ के स्तरोन्नयन कार्य तथा चंगर क्षेत्र बड़ोह में घरेलू पेयजल कनेक्शन मुहैया कराने की 6.44 करोड़ रुपये की परियोजना का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने बनेर खड्ड पर जसोर गांव के लिए 3.50 करोड़ रुपये से बने स्पैन ब्रिज का उद्घाटन किया। उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बालूग्लोआ में 1. 10 करोड़ रुपये से निर्मित विज्ञान प्रयोगशाला और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक छात्र पाठशाला नगरोटा बगवां में 1.54 करोड़ रुपये से बने अतिरिक्त भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने मेडिकल कॉलेज टांडा में 2.95 करोड़ रुपये से बने सुविधा खंड कम कैंटीन का लोकार्पण भी किया।

नगरोटा बगवां व पालमपुर शहर के लिए करीब 52–52 करोड़ रुपये की सौंदर्यीकरण परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने नगरोटा बगवां के लिए 130 करोड़ रुपये की वेलनेस कम कनवेंशन सेंटर एवं का वेडिंग डेस्टीनेशन तथा इंटरनेशनल फाउंटेंन परियोजना शिलान्यास किया। इसमें 90 करोड़ रुपये वेलनेस कम कनवेंशन सेंटर तथा वेडिंग डेस्टीनेशन पर और 40 करोड़ रुपये इंटरनेशनल फाउंटेंन के निर्माण पर व्यय होंगे।

उन्होंने नगरोटा बगवां स्थित मधुमक्खी पालन केंद्र के विकास की 8.51 करोड रुपये की परियोजना और 1.90 करोड़ रुपये लागत से बनने वाले विद्युत बोर्ड के डिविजन एवं सब डिविजन के भवन की आधारशिला रखी।

मुख्यमंत्री ने 2.74 करोड़ रुपये की धनूल–काशतवाड़ी सिंचाई परियोजना, 3.62 करोड़ रुपये की कठूल कुहल परियोजना और 1.23 करोड़ रुपये की मटयाड़ी में जल स्रोत सुधार कार्य परियोजना का शिलान्यास किया।

उन्होंने 8.46 करोड़ रुपये के देहरियां कंडी घराणा सड़क स्तरोन्ययन कार्य तथा 7.24 करोड़ रुपये के ठंडा पानी, जगनी से खब्बलखोली खरट सड़क, 5.04 करोड रुपये से कंडी से सरूट सड़क तथ 9.64 करोड़ रुपये के नगरोटा बलधर सियूण पधर सड़क के स्तरोन्नयन कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने नगरोटा बगवां के रनहू में 5 करोड़ रुपये से बनने वाले राजीव गांधी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने 7.52 करोड़ रुपये से बनने वाली टोरू–वाह–चपरेहड़ सड़क का शिलान्यास किया। उन्होंने 14.14 करोड़ रुपये से टांडा मेडिकल कॉलेज में बनने वाले लेक्चर थियेटर परिसर और 27.44 करोड़ रुपये से नगरोटा बगवां में बनने वाले पार्किंग परिसर एवं सामुदायिक केंद्र की आधारशिला रखी। उन्होंने नगरोटा बगवां के हटवास में 4.75 करोड़ रुपये से बनने वाले इंडोर खेल परिसर का शिलान्यास किया।

1962 मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा का शुभारम्भ किया मुख्यमंत्री ने

vkdlk f'keykA मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पशुपालन विभाग की 1962–मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा का शुभारंभ किया, जिसके तहत प्रथम चरण में 44 विकास खंडों में एंबुलेंस उपलब्ध करवाई गई हैं। इस पर 7.04 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की गई है। इनमें से बिलासपुर, ऊना, सोलन व कुल्लू में तीन–तीन, लाहौल–स्पीति में दो, मंडी व शिमला में पांच, चंबा, सिरमौर व हमीरपुर में चार–चार, किन्नौर में एक तथा कांगड़ा जिला में सात मोबाइल एंबुलेंस उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने पशु संजीवनी कॉल सेंटर का शुभारम्भ भी किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दोनों सेवाओं के आरंभ होने से प्रदेश के पशु पालक किसी भी कोने से टोल फ्री नंबर 1962 पर कॉल कर आपात स्थिति में गंभीर पशु रोगों के उपचार के लिए पशु चिकित्सा सेवा अपने घर–द्वार पर प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक एंबुलेंस के साथ एक पशु चिकित्सक तथा एक फार्मासिस्ट उपलब्ध होंगे।

जब भी किसी पशु पालक को आपात स्थिति में मदद चाहिए होगी, तो वह टोल फ्री नंबर 1962 पर कॉल कर सकेंगे और उन्हें नजदीकी पशु चिकित्सा सेवा के माध्यम से सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में पशु चिकित्सा सेवा किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः नौ बजे से सायं पांच बजे तक उपलब्ध रहेगी।

उन्होंने कहा कि भविष्य में चरणबद्ध तरीके से इस सेवा का विस्तार किया जा रहा है।

प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के अधीन विशेषज्ञों से ली जानकारी सेब बागवानों ने

vkdlk f'keykA सेब बागवानी में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बुधवार को कृषि विभाग की आतमा शिमला टीम की ओर से एक दिवसीय कार्यशाला का मशोबरा में आयोजन किया गया। सेब बागवानों के लिए आयोजित कार्यशाला और किसान–वैज्ञानिक परिचर्चा में बाग. वानी वैज्ञानिक डॉ उषा शर्मा ने बाग. वानों को प्रा.तिक खेती विधि से सेब की बेहतर पैदावार लेने के बारे में विस्तार से जानकारी दी। डॉ उषा ने कहा कि वे पिछले चार वर्षों से प्राकृतिक खेती विधि से सेब बागवानी पर शोध कर रही हैं। उन्होंने बताया कि इस खेती विधि में उन्हें बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। उन्होंने कहा कि इस खेती विधि को अपनाने के बाद हमारा बंजर पड़ा सेब का बाग भी अच्छी पैदावार देने लगा है। इसे अपनाने से मित्र कीटों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, बीमारियां कम आ रही हैं और विपरीत परिस्थितियों में भी फसलें अच्छी पैदावार दे रही हैं। डॉ उषा का कहना है कि उन्होंने अपने शोध के दौरान प्राकतिक खेती विधि को अपनाने के बाद मिट्टी की गुणवता, सेब की पैदावार और गुणवत्ता को बेहतर पाया है। इसलिए उन्होंने किसान–बागवानों से अनुरोध किया कि वे भी इस खेती विधि को थोड़े से भू–भाग में प्रयोग के तौर पर शुरू करके इसका दायरा बढ़ाएं।

इस कार्यशाला के दौरान कृषि अर्थशास्त्री डॉ मनोज गुप्ता ने प्राकृतिक खेती के ऊपर विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं की ओर से किए गए विभिन्न अध्ययनों की जानकारी दी। मनोज गुप्ता ने प्राकृतिक खेती किसानों के प्रमाणीकरण को लेकर की गई नई पहल के बारे में भी बागवानों को जानकारी दी। इस दौरान प्राकृतिक खेती कर रहे विभिन्न किसान–बाग. वानों ने अपने अनुभव भी साझा किए। नारकंडा विकास खंड के तिलक राज ने बताया कि वे पिछले पांच वर्षों से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और उनकी पैदावार अच्छी आ रही है। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपना प्रमाणीकरण भी करवाया है और इस प्रमाणपत्र की वजह से उन्हें अपने सेब और प्लम के अच्छे दाम मिल रहे हैं।

कार्यशाला के आयोजक प्रोजेक्ट डायरेक्टर आतमा शिमला, डॉ देवीचंद कश्यप ने बताया कि इस कार्यक्रम के पीछे मुख्य उदेश्य किसान–बागवानों को प्राकृतिक खेती विधि के ऊपर हुए शोध कार्य के बारे में अवगत करवाना था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती विधि से भी अच्छी तरह से सेब बागवानी हो सकती है इसके बारे में वैज्ञानिकों से जानकारी प्राप्त करने के बाद बागवानों के कई भ्रम खत्म हुए हैं। इससे वे प्राकृतिक खेती को अच्छी तरह से अपने खेत बागीचे में उतार सकेंगे।

मशोबरा के समेती संस्थान में आयोजित इस कार्यशाला में शिमला जिला के सभी विकास खंडों के 130 से अधिक सेब बागवानों ने भाग लिया।

प्रदेश सरकार महिलाओं और बालिकाओं के जीवन में गुणात्मक सुधार के लिये कृतसंकल्प : डॉ शांडिल

vkdlk f'keykA सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल डॉ. धनी राम शांडिल ने कहा कि महिलाओं और बालिकाओं के जीवन में गुणात्मक सुधार के लिये प्रदेश सरकार . तसंकल्प है। उन्होंने कहा कि आज समय है की हम प्रत्येक महिला का सम्मान करने और उन्हें आगे बढने के लिए प्रेरित करने का संकल्प लें।

डॉ. शांडिल यहाँ अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में बतौर मुख्यातिथि उपस्थित लोगों को सम्बोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी महिलाओं को सशक्त बनाने की है। इसी दिशा में वर्तमान प्रदेश सरकार ने प्रदेश की 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह देने की घोषणा की है।

डॉ. शांडिल ने कहा कि आज के समय में लड़कियाँ और महिलायें किसी से कम नहीं हैं और उन्होंने अपनी उपलब्धियों से पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री शगुन योजना, बेटी है अनमोल योजना, विधवा पुनर्विवाह योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि योजनाएँ सरकार द्वारा चलाई जा रही है।

राजनीति में भी आगे आएं महिलाएं

कैबिनेट मंत्री ने महिलाओं से राजनी. ति के क्षेत्र में भी सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश विधान सभा में केवल एक महिला विधायक है जबकि महिलाओं की भागीदारी बराबर होनी चाहिए। इसलिए प्रदेश की महिलाआ. ं को राजनीति में भी आगे आना चाहिए।

विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने वाली महिलाओं को किया सम्मानित

हिमाचल प्रदेश महिला विकास प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कला एवं संस्ति के क्षेत्र में वर्षा कटोच पुत्री नरेश चंद कटोच गांव टी इस्टेट जिक्कर, डाकघर व तहसील कांगड़ा, जिन्होंने पिछले 5 वर्षो से महिला उत्थान व सशक्तिकरण के लिए अलग–अलग कार्य किये है। इन्हें विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है तथा हिमाचल प्रदेश कला साहित्य अकादमी द्वारा भी सम्मानित किया गया है। सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में अनिता वीपीओ कलाथ, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, इनके द्वारा 2013 से 21 वृद्ध जनों को खाना, आश्रय व स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही है साथ ही 40 मंदबुद्धि महिलाओं को भी भोजन व आश्रय प्रदान किया गया है। इनके द्वारा 6 स्वयं सहायता समूह भी चलाए जा रहे है तथा दिपाला चौहान, वीप. ीओ पुजारली नं.4, तहसील रोहडू, जिला शिमला, इनके द्वारा छोड़े गए बेजुबान जानवरों का रेसक्यू कर उन्हें आश्रय, चारा व अन्य आवश्यक उपचार दिया जा रहा है, को सम्मानित किया गया।

मुख्यमंत्री शगुन योजना के अंतर्गत सोलन जिला की लाभार्थी कृष्णा देवी, चम्पा देवी, कुसुम देवी, शीला देवी तथा सीता देवी व शिमला जिला के बसन्तपुर से लाभार्थी प्रकाश, हरी नंद तथा जोगिन्द्र सिंह एवं जुब्बल से लाभार्थी सोहन लाल व मोहिन्द्र सिंह को 31–31 हजार रूपए के चेक भेंट कर सम्मानित किया गया।

इसी प्रकार, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत सोलन जिला के लाभार्थी कामिनी देवी, सुख देव व अंजली व शिमला जिला के बसन्तपुर से लाभार्थी नीली देवी, ठियोग से सुभद्रा देवी, मशोबरा से शीला देवी, रोहडू से ध्यांकु देवी व मीरा को 51–51 हजार रुपए के चेक भेंट कर सम्मानित किया गया।

मुख्यातिथि ने विधवा पुनर्विवाह योजना के अंतर्गत शिमला जिला के कुमारसैन से सरिता व ठियोग से रेखा को 2–2 लाख रुपए के चेक भेंट कर सम्मानित किया।

उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में जिला बिलासपुर के सदर खण्ड से बबली, जिला चम्बा के चौवारी खण्ड से दीपशिखा, हमीरपुर से नीलम कुमारी, कुल्लू के बंजार खण्ड से इशारा देवी, नानास्पो किन्नौर निचार के भावानगर से प्रभा रानी, कांगड़ा के रैत से रजनी देवी, लाहौल के केलांग से सुनिता देवी, मण्डी के करसोग से कुसुमा देवी, शिमला के बसन्तपुर से गुलाब देई, सोलन के नालागढ़ से मीता रानी, सिरमौर के संगराह से निशा राणा तथा ऊना से जीवन लता को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। इसी प्रकार, उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनबाड़ी सहायिकाओं में जिला बिलासपुर के सदर से निर्मला देवी, चम्बा के चौवारी से कांता देवी, हमीरपुर के नादौन से सुमना देवी, कुल्लू के आनी से रीना देवी, किन्नौर के दुबलिंगपुल पूह से वीना कुमारी, कांगड़ा के रैत से पुष्पा देवी, लाहौल–स्पीति के केलांग से निर्मला, मण्डी के करसा. ंग से प्रेमी देवी, शिमला के कुमारसैन से सरला, सोलन के नालागढ़ से आशा रानी, सिरमौर के संगराह से ममता तथा ऊना से प्रवीन कुमारी को भी प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया।

विभिन्न प्रतियोगिताओं की विजेताओं को दिए नकद इनाम

इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई गई जिनके विज. ंताओं को मुख्य अतिथि ने नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। रंगोली प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पवना और उषा, द्वितीय स्थान सुनीता और तृतीय स्थान वीना और पुष्पा ने हासिल किया। इसी प्रकार, रस्साकशी में पहला स्थान कांता बेक्टा और टीम तथा दूसरा स्थान अनीता और टीम ने हासिल किया। म्यूजिकल चेयर में पहला स्थान कांता बेक्टा, दूसरा भावना गोयल तथा तीसरा स्थान अंजना ने हासिल किया। सुई धागा दौड़ में प्रथम स्थान पर कांता बेक्टा, द्वितीय स्थान पर इंद्रा ठाकुर और तृतीय स्थान पर अंजना रही। मेहंदी प्रतियोगिता में भावना गोयल, मीनाक्षी सूद और चंपा ने क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। रंगोली प्रतियोगिता में पुष्पा व उषा ने पहला स्थान, सुनीता ने दूसरा स्थान तथा वीना व पुष्पा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।

इसी प्रकार लेमन स्पून रेस में पहला स्थान कांता बेक्टा, ममता ने दूसरा और मीनाक्षी सूद ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।

इससे पूर्व उन्होंने इस अवसर पर लगाई गई प्रदर्शनियों का अवलोकन भी किया और मिशन शक्ति के तहत स्टेट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ़ वीमेन के लिए दो वाहनों को हरी झंडी भी दिखाई जिसमें एक वाहन राज्य स्तर पर और दूसरा जिला शिमला में व्यथित महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए उपयोग की जाएँगी।

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिका. रिता विभाग एम सुधा देवी ने स्वागत संबोधन प्रस्तुत किया।

निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, रूपाली ठाकुर ने धन्यवाद संबोधन प्रस्तुत किया।

इस अवसर पर डॉ. दीपाली, महापौर नगर निगम शिमला सुरेंद्र चौहान, उपमहापौर उमा कौशल, निदेशक स्वास्थ्य सेवाएँ डॉ. गोपाल बैरी सहित, विभाग के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

e[;e=h us ,f'k;u fjoj jkfVx pkfEi;uf'ki dk 'kHkkjHk fd;k

vkdlk f'keykA मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से 4 से 9 मार्च, 2024 तक बसंतपुर के निकट सतलुज नदी में आयोजित की जा रही एशियन रिवर राटिंग चौम्पियनशिप में भाग लेने वाली टीमों को हरी झंडी दिखाकर चौम्पियनशिप शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ईरान, इराक, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान तथा इंडोनेशिया सहित 20 टीमें भाग ले रही है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। हाल ही में जिला हमीरपुर के नादौन में राटिंग मैराथन और गत वर्ष जिला शिमला के जुन्गा में पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया। राज्य में लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए साहसिक खेल गतिविधियों का आयोजन करवाया जा रहा है। इससे प्रदेश ने राजस्व बढ़ौतरी के साथ–साथ लोगों की आर्थिकी भी सु. ढ़ होती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार है इससे हजारों परिवार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पर्यटन क्षेत्र की अधोसंरचना को मजबूत कर राज्य में पर्यटकों की आवाजाही को बढ़ाने के लिए दृढ़ प्रयास कर रही है ताकि एक वर्ष में पांच करोड़ पर्यटकों के आगमन का लक्ष्य हासिल किया जा सके।

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, मुख्य संसदीय सचिव मोहन लाल ब्राक्टा, विधायक हरीश जनारथा, हिमाचल राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष देवेन्द्र श्याम, प्रदेश राज्य वन विकास निगम के उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची, नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान, निदेशक पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मानसी सहाय ठाकुर, उपायुक्त अनुपम कश्यप और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने किए नेरवा में 73-43 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास

vkdlk ujok@pkikyA मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला जिला के चौपाल के नेरवा में 73.43 करोड़ रुपये की विभिन्न योजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास करने के उपरान्त एक विशाल जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार नवीन योजनाओं के माध्यम से राज्य के जन–जन के जीवन स्तर में सुधार के लिए कार्यरत है।

मुख्यमंत्री ने 5.10 करोड़ रुपये की लागत से कनाहल से बजाथल, 5.14 करोड़ रुपये की लागत से सैंज से डाक सराड़, 6.83 करोड़ रुपये की लागत से तराहं से बनाह, 6.89 करोड़ रुपये की लागत से पबास से मशरौंह, 4.01 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित ननहार से मलकौत मार्ग वाया कुटू कलून हरिजन बस्ती सड़क तथा नानू कुठाड़ बासाधार गियान कोट मार्ग पर 2.95 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित पुल का लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री ने न्योटी छावनी बावी मार्ग पर न्योटी में शालू खड्ड पर 4.36 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले 60 मीटर लम्बे प्रीस्ट्रैस्ड डबल लेन पुल का शिलान्यास किया। उन्होंने 30.46 करोड़ रुपये की लागत से खिड़की से चौपाल मार्ग को चौड़ा करने एवं सु.ढ़ीकरण कार्य की आधारशिला भी रखी। उन्होंने 7.68 करोड़ रुपये की लागत से देहा कठोरी पुंडर घलाना मार्ग के स्तरोन्नयन कार्य का शिलान्यास भी किया।

सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार जन हितैषी सोच के साथ न केवल योजनाओं को धरातल पर उतार रही है अपितु चुनाव पूर्व लोगों के साथ किए गए वायदों को कठिन वित्तीय स्थिति के बावजूद भी पूरा कर रही है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने गत दिवस प्रदेश की 18 वर्ष से अधिक आयुवर्ग की महिलाओं को इन्दिरा गांधी प्यारी बहना सुख–सम्मान निधि योजना के तहत 1500 रुपये मासिक प्रदान करने की घोषणा कर अपनी पांचवी गारंटी पूरी की है। इस योजना के कार्यान्वयन पर 800 करोड़ रुपये वार्षिक खर्च होंगे और इस निर्णय से प्रदेश की लगभग पांच लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत शीघ्र ही फार्म भरने की प्रक्रिया आरम्भ होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सत्ता सम्भालते ही कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने की .ष्टि से न्यू पेंशन योजना के 1.36 लाख सरक. ारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्रदान कर अपनी प्रथम गारंटी पूरी की और ऐसे सभी कर्मचारियों के सम्मान जनक जीवन जीने के सपने को पूरा किया। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी विद्यालयों में पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम शुरू करने की गारंटी हिमाचल के भविष्य को आत्मविश्वास के साथ आगे बढने में सहायता करेगी।

उन्होंने कहा कि प्रदेश की सभी महिलाओं को आत्मसम्मान के साथ जीने का अधिकार देना प्रदेश सरकार का लक्ष्य है। राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत दी जा रही दिहाड़ी में 60 रुपये की वृद्धि की है। अब मनरेगा दिहाड़ी के तहत 300 रुपये मिलेंगे। सेब का समर्थन मूल्य भी आशातीत बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि चौपाल क्षेत्र में भारी वर्षा के समय प्रदेश सरकार ने अवरुद्ध सड़कों को खोलने पर 15 करोड़ रुपये व्यय किए ताकि बागवानों का सेब समय पर मण्डियों तक पहुंचे।

सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि गाय के दूध के क्रय मूल्य को 32 रुपये से बढ़ाकर 45 रुपये प्रति लीटर तथा भैंस के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाकर 55 रुपये प्रति लीटर कर चौथी गारंटी पूरी की गई है। उन्होंने कहा कि प्रा.तिक खेती के माध्यम से प्राप्त गेहूं और मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है।

उन्होंने कहा कि प्रदश सरकार न केवल अपनी प्रत्येक गारंटी को पूरा करेगी बल्कि नवीन योजनाओं के माध्यम से वर्ष, 2027 तक प्रदेश को देश का समृद्धतम राज्य बनाने के सपने को भी साकार करेगी।

सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अभी कुछ दिन पूर्व प्रदेश की लो. कतांत्रिक सरकार को अनैतिक तरीक. ों से गिराने के भाजपा के कुत्सित प्रयास को सभी ने देखा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के ऐसे इरादे कभी सफल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार एकजुट होकर आत्मनिर्भर हिमाचल के निर्माण के लिए कार्यरत है और जन कल्याण की राह में आ रही सभी बाधाओं को हटाने में देरी नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वह 45 वर्षों से भी अधिक समय से राजनीति के माध्यम से प्रदेश वासियों की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपने प्रदेश के लोगों के जीवन में आशातीत सुधार करने के अपने प्रयास वह सदैव जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि मैं एक योद्धा हूं और संघर्ष की भट्टी में तपकर जन सेवा के लिए सदैव तत्पर हूं।

उन्होंने इस अवसर पर नेरवा में बहुमंजिला बस अड्डा निर्मित करने, नेरवा में दुग्ध शीतन केन्द्र स्थापित करने, नेरवा में मिनी सचिवालय स्थापित करने, अग्निश्मन केन्द्र खोलने तथा राजकीय महाविद्यालय नेरवा में दो विषयों में पी.जी. कक्षाएं आरम्भ करने की घोषणाएं की। उन्होंने नेरवा में इंडोर खेल स्टेडियम के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपये प्रदान करने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि कुपवी में लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के दृष्टिगत मिनी सचिवालय खोला जाएगा। उन्होंने क्षेत्र के धारचांदना, देईया, नेवटी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की घोषणा की। उन्होंने चौपल व नेरवा स्थिति नागरिक अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड सुविधा शीघ्र उपलब्ध करवाने का आश्वासन भी दिया।

इससे पूर्व चौपाल उपमंडल के नेरवा पहुंचने पर मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। पारंपरिक ठोडा नृत्य के साथ सुखविंदर सिंह सुक्खू का हजारों की संख्या में उपस्थित जनता ने पहाड़ी परंपरा के साथ स्वागत किया। चौपाल विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार रहे रजनीश खिमटा ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं। उन्होंने चौपाल विधानसभा क्षेत्र के विकास को गति प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

सरकार शुरू करे अफीम की खेती, नहीं तो कम से कम ठेका ही खोले-विधानसभा में आप विधायक की मांग

pMhx<A पंजाब विधानसभा में गुरुवार को बजट सत्र के पांचवें दिन सत्ताधारी पार्टी के विधायकों ने सिंथेटिक ड्रग पर नकेल कसने के लिए प्रदेश में अफीम की खेती शुरू करने और अफीम के ठेके खोलने की मांग की। आप विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा द्वारा सदन में यह मुद्दा उठाने पर पूरे सदन में पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवां ने भी हंसते हुए पठानमाजरा से कहा कि वह एक–दो दिन में उन्हें यह रिपोर्ट उपलब्ध कराएं कि पंजाब में पहले–पहल चलने वाले अफीम के ठेकों को कब और क्यों बंद किया गया था।

अफीम की खेती और ठेके खोलने के बारे में पठानमाजरा ने सरकार से सवाल किया कि राज्य सरकार सूबे में अफीम की खेती करने पर विचार कर रही है? उन्होंने कहा कि आज स्मैक और नशीली गोलियों के कारण फैले नशे की वजह से पंजाब की जवानी खत्म हो रही है। पुराने लोग जो रिवायती नशे करते थे, वह उसके साथ अपने सभी काम भी करते थे। खेती भी करते थे और आज तक ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई कि अफीम या भुक्की खाने से किसी की मौत हुई हो।

पठानमाजरा ने यह भी कहा कि अगर पंजाब सरकार की खेती शुरु करने की कोई योजना नहीं है तो अफीम के ठेके जरूर खोले जाएं। पठानमाजरा द्वारा उठाए गए मुद्दे का समर्थन करते हुए आप विधायक मनजीत सिंह बिलासपुर ने कहा कि बीते 15 साल से पंजाब चिट्टे की समस्या से जूझ रहा है, जिसने पंजाब की नौजवानी को बड़ा नुकसान पहुंचाया है।

उन्होंने कहा कि सरकार को अफीम की खेती शुरू करने पर विचार करना चाहिए, क्योंकि वैद्य और डॉक्टर भी अब कई बीमारियों में इसका सेवन करने की सलाह देते हैं। विधायक कुलवंत सिंह बाजीगर ने भी अफीम की खेती की मांग करते हुए कहा कि सिंथेटिक ड्रग ने पंजाब में बड़ी संख्या में घर बर्बाद कर दिए हैं और कई माताओं ने बेटे गंवा दिए हैं। बाजीगर ने कहा कि उन्हें लगता है कि सभी सदस्य भी इसके पक्ष में हैं।

इस पर .षि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने मुस्कुराते हुए कहा कि हालांकि इस मांग से सभी सदस्य सहमत नजर आ रहे हैं।

विपक्ष के सदस्य भी बोल नहीं रहे लेकिन सहमत दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि वैसे उनकी उम्र भी उस तरफ जा रही है, जहां उन्हें भी इसकी जरूरत पड़ सकती है लेकिन फिलहाल सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है।

उन्होंने कहा कि सरकार इसकी खेती को भी एक तरह का नशा मानती है।

परिवार की याद आती है इसलिए छोड़ा पद : प्रशासक बनवारी लाल

pMhx<A चंडीगढ़ प्रशासन ने कुछ दिन पहले आदेश जारी कर वर्ष 2008 की यूटी इंप्लाइज हाउसिंग स्कीम को रद्द कर दिया था लेकिन गुरुवार को प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित ने कहा कि यह योजना बंद नहीं की गई है। अगर ऐसा है भी तो कर्मचारियों के हित में एफिडेविट बदल दिया जाएगा। कलेक्टर रेट पर सहमति बनी तो 4000 कर्मचारियों को कम कीमत पर लैट मुहैया करवाए जाएंगे। इन्हें किफायती बनाने के लिए जरूरत पडने पर री–डिजाइन भी किया जाएगा। प्रशासक ने कहा कि कर्मचारी हमारी प्राथमिकता में हैं।

यूटी प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित इस्तीफा देने के बाद पहली बार यूटी सचिवालय में मीडिया रूबरू हुए। प्रेसवार्ता में उन्होंने स्पष्ट किया कि इस्तीफे की वजह केवल पारिवारिक थी, जिसे राष्ट्रपति भवन द्वारा स्वीकार नहीं किया गया इसलिए पंजाब और चंडीगढ़ की सेवा में लगा हूं। कहा कि वह नागपुर में अपने परिवार को बहुत याद करते हैं। पत्नी और परिवार चाहता है कि वह घर पर आराम करें। पिछले दिनों उनकी धर्मपत्नी राजभवन आईं तो 24 घंटे का काम देखते हुए परेशान होकर यहां से चली गईं।

पुरोहित ने कहा कि श्मैं भारतीय विद्या भवन का अंतरराष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं। संस्थान में हजारों बच्चे शिक्षा ले रहे हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहा है। मैं सभी को बहुत याद करता हूं। अब उम्र भी ज्यादा हो गई है इसलिए इस्तीफा दिया था जो स्वीकार नहीं हुआ।च प्रशासक ने अपने करीब ढाई साल के कार्यकाल में शहर की उपलब्धियां गिनाईं। यूटी के अधिकारियों की टीम की पीठ थपथपाते हुए कहा कि उन्हें दूसरे राज्यों में भी बतौर राज्यपाल काम करने का अवसर मिला लेकिन चंडीगढ़ की टीम बेस्ट टीम है। अधिकारी देर रात तक काम करते हैं और उनके खाते में उपलब्धियां भी हैं। अंदरखाते अधिकारियों को डांट भी देता हूं लेकिन बेहतर करने पर पीठ भी ठोकता हूं।

कहा– निगम से सीधा वास्ता नहीं, लेकिन एफएंडसीसी के बिना पास नहीं होता बजट

नगर निगम की बैठक रद्द होने के बावजूद मेयर द्वारा बजट पारित करने के मुद्दे पर प्रशासक पुरोहित ने कहा कि उनका नगर निगम से सीधा लेना–देना नहीं लेकिन उनके पास शिकायत आई तो इस संबंध में निर्देश जारी किए गए। निगम के आयुक्त को इसके लिए बोला गया कि जो भी आवश्यक हो अपने हिसाब से कार्रवाई करें। एफएंडसीसी की बैठक के बिना बजट पारित नहीं होता। इसके बावजूद बैठक आयोजित करना बचपना है।

पंजाब विधानसभा सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान व्यवधान को लेकर एक सवाल के जवाब में राज्यपाल ने कहा कि उनका काफी लंबा राजनीतिक कॅरिअर रहा है। वह समय भी देखा जब सत्र चलाने के लिए पैसे भी नहीं होते थे इसलिए सभी विधायकों और सांसदों को सत्र के समय का सदुपयोग करना चाहिए क्योंकि इसके संचालन पर काफी खर्च आता है।

सत्र में इस तरह से व्यवधान डालना किसी भी तरह से ठीक नहीं। पक्ष हो या विपक्ष, सभी को इसका ध्यान रखना चाहिए।

सुशासन से खात्म हुआ भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचारी कानून के शिकंजे में : जगदीप धनखड़

pMhx<A पंजाब विश्वविद्यालय के 71वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सड़क पर उतरकर कानून में व्यवधान पैदा कर रहे, यह चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि ऐसे चलन को बेअसर करना जरूरी है। आपकी पहली व आखिरी पहचान भारतीय ही होनी चाहिए। मेरी पीढ़ी ने भाई–भतीजावाद और पक्षपात को देखा है। आप भाग्यशाली हैं जो इस समय में हैं, जब परिवारवाद और भाई–भतीजावाद को सुशासन व नीति निर्माण से समाप्त किया गया है। भ्रष्टाचार करने वाले कानून के शिकंजे में हैं। ये बातें गुरुवार को पंजाब विश्वविद्यालय (पीयू) के 71वें दीक्षांत समारोह के दौरान विद्यार्थियों को संबो. धित करते हुए उपराष्ट्रपति व पीयू के कुलाधिपति जगदीप धनखड़ ने कहीं।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि सुशासन और नीति निर्माण के चलते आज युवाओं के सामने विभिन्न क्षेत्रों में कई असवर उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि एक समय था जब शासन भ्रष्टाचार से ग्रसित था। भ्रष्टाचार ही नौकरी और अवसर प्राप्त करने का पासवर्ड था लेकिन आज भ्रष्टाचारी कानून के शि. कंजे में हैं।

उपराष्ट्रपति ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि यह चकित कर देने और चिंता की बात है कि लोकतंत्र के महत्वपूर्ण हितधारक होने के बावजूद कुछ लोग सड़कों पर उतरकर कानून में व्यवधान पैदा कर रहे हैं। युवाओं को प्यारे दोस्त के रूप में संबोधित करते हुए धनखड़ ने कहा कि ऐसे चलन को बेअसर करना जरूरी है। देश में कानून का होना लोकतंत्र के लिए मौलिक है जो बराबरी के अधिक. ार को पूरा करता है।

उपराष्ट्रपति ने कहा हाल ही में लो. कतंत्र के मंदिरों, संसद पर कुछ ने हमला किया। देश में कुछ राष्ट्र विरा. `धी तत्व हैं जो देशभक्ति की भावना और विकास में खलल डाल रहे हैं। जहां देश के विकास की बात आती है वहां

उन्होंने विश्वविद्यालय वह महत्वपूर्ण स्थान है जहां युवा विभिन्न मुद्दों पर खुलकर बात कर सकते हैं लेकिन हमेशा देश को पहले रखें। धनखड़ ने डॉ. बीआर आंबेडकर का उल्लेख करते हुए कहा कि आपकी पहली पहचान भारतीय होनी चाहिए, आखिरी पहचान भी भारतीय होनी चाहिए और कुछ नहीं।

3623 करोड़ की सौगात मिली हरियाणा को,सीएम ने किया 679 परियोजनाओं का उदघाटन व शिलान्यास

pMhx<A लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा को लगभग 3623 करोड़ रुपये की 679 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। पंचकूला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 20 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। बाकी योजनाओं के लिए राज्य के सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां मंत्री, सांसदों व विधायकों ने परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम ने 59 मॉडल प्ले–वे स्कूलों का भी उद्घाटन किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महाशिवरात्रि व अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई दी और कहा कि इस प्रकार के वर्चुअल माध्यम से एक साथ सभी जिलों के लिए परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास के अब तक आठ कार्यक्रम हो चुके हैं। यह नौंवा कार्यक्रम था। 10वां कार्यक्रम मई या जून माह में किया जाएगा, उस समय भी करोड़ों रुपये की परियोजनाएं जनता को समर्पित की जाएंगी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हरियाणा की विकास दर 8 फीसदी है, जो राज्य की प्रगति को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग की वर्ष 2023 में आई रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा ऐसा राज्य है, जहां 14 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं।

पंजाब का राजकोषीय घाटा 47–48 फीसदी तक

पंजाब सरकार को आड़े हाथो लेते हुए उन्होंने कहा हरियाणा का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के पैरामीटर के अनुसार 26–27 फीसदी तक है जबकि पंजाब सरकार की ओर से पेश किए बजट में राजकोषीय घाटा 47–48 प्रतिशत तक दिखाया गया है। अब पंजाब के लोग भी मानते हैं कि हरियाणा उनसे बहुत आगे निकल गया है।

सीएम मनोहर लाल ने कहा कि 11 मार्च को पीएम मोदी द्वारका एक्सप्रेस–वे का उद्घाटन करेंगे। यह लगभग 7000 करोड़ रुपये की परियोजना है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया।

इन परियोजनाओं का किया शिलान्यास व उद्घाटन

214 करोड़ रुपये की लागत से फरीदाबाद में दिल्ली–आगरा –दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस–वे बल्लभगढ़ मोहना रोड़ पर चार लेन एलिवेटिड सड़क की आधारशिला।

करनाल में 127 करोड़ रुपये की लागत से खालसा चौक से हरियाणा नर्सिंग होम तक के लाईओवर की आधारशिला।

महेंद्रगढ़ में 114 करोड़ रुपये की लागत से अटेली मंडी में 61 गांवों के लिए नहर आधारित जलापूर्ति योजना का उद्घाटन।

चरखी दादरी में 112 करोड़ रुपये की लागत से निमर बाढेसरा में 35 गांवा. ं के लिए जलापूर्ति योजना का उद्घाटन।

फतेहाबाद में 100 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली जेल का शिलान्यास।

पंचकूला में 87 करोड़ रुपये की लागत से ट्रांसपोर्ट भवन का शिलान्यास।

बिलासपुर में 87 करोड़ रुपये की लागत से खोजकीपुर को जोडने के लिए यमुना नदी पर एचएलब्रिज का निर्माण।

रोहतक में 65 करोड़ रुपये की लागत से सुखपुरा चौक पर लाईओवर व 61 करोड़ रुपये की लागत से ओल्ड हाउ. सिंग बोर्ड कॉलोनी की आधारशिला।

नूहं में नए 126 घरों के निर्माण की आधारशिला।

60 करोड़ रुपये की लागत से झज्जर–कोसली सड़क का सु. ढ़ीकरण।

सोनीपत में 59 करोड़ रुपये की लागत से डॉ. बीआर अंबेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में नये ऑडिटोरियम भवन की आधारशिला।

हिसार में 55 करोड़ रुपये की लागत से बरवाला में जलापूर्ति योजना का संवर्धन।

53 करोड़ रुपये की लागत से रेवाड़ी–बावल सड़क का सुधार।

51 करोड़ रुपये की लागत से महम–कलानौर सड़क के सुधार कार्य का शिलान्यास।

46 करोड़ रुपये की लागत से पीजीआईएमएस रोहतक में गर्ल्स हॉस्टल की आधारशिला।

जींद में 39 करोड़ रुपये की लागत से सामुदायिक सोलर ग्रिड पॉवर सूक्ष्म सिंचाई प्रोजेक्ट की आधारशिला।

36 करोड़ रुपये की लागत से राज्य सूचना आयोग हरियाणा के भवन का उद्घाटन।

36 करोड़ रुपये की लागत से पीजीआईएमएस रोहतक में ब्वॉज हॉस्टल।

कैथल में 32 करोड़ रुपये की लागत से कैथल के लाडना चक्कू में राजकीय कन्या महाविद्यालय की आधारशिला।

हिसार के गांव डाटा में राजकीय कन्या महाविद्यालय का शिलान्यास।

मंत्री अनमोल गगन मान को मिला वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ ईयर सम्मान

pMhx<A पंजाब की पर्यटन मंत्री अनमोल गगन मान को गुरुवार को जर्मनी की राजधानी बर्लिन में आयोजित पर्यटन उद्योग से संबंधित अंतरराष्ट्रीय स्तर के समागम में पर्यटन के क्षेत्र में सराहनीय भूमिका निभाने के लिए च्वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ ईयरच्य खिताब से सम्मानित किया गया। इसके अलावा पंजाब राज्य ने फार्म और रुरल टूरिज्म अवॉर्ड भी जीतने में सफलता हासिल की है।

इंटरनेशनल टूरिज्म बोरिस बर्लिन (आईटीबी बर्लिन) और दी पैसेफिक एरिया ट्रेवल राइटर्ज एसोसिएशन (पाटवा) द्वारा संयुक्त तौर पर करवाए गए इस तीन दिवसीय समागम के दौरान दुनिया भर के पर्यटन उद्योग से जुड़ी कंपनियों और संस्थाओं ने हिस्सा लिया। कैबिनेट मंत्री अनमोल गगन मान ने कहा कि राज्य में पर्यटन उद्योग को प्रफुल्लित करने के लिए किए जा रहे प्रयास के लिए यह सम्मान मिला है। सम्मान हासिल करने के उपरांत अनमोल गगन मान ने कहा कि पंजाब राज्य में पर्यटन उद्योग की बहुत संभावनाएं हैं, जिसक. ो सिर्फ मूलभूत ढांचा देने और प्रचार करने की जरूरत है और सरकार इसी दिशा में काम कर रही है।

क्यों इतनी चर्चा में है एचपीवी वैक्सीन? किस कैंसर से बचाव के लिए इसे माना जा रहा है रामबाण

वैक्सीनेशन, किसी विशेष रोग से होने वाली जटिलताओं से बचाने का सबसे प्रभावी तरीका मानी जाती है। बच्चों को कई प्रकार की गंभीर बीमारियों के खतरे से सुरक्षित रखने के लिए जन्म के बाद नियमित अंतराल पर टीकाकरण कराने की सलाह दी जाती है। कोरोना महामारी के दौरान भी व्यापक टीकाकरण अभियान के ही परिणामस्वरूप रोग पर काफी हद तक काबू पाया गया।

इन दिनों एचपीवी वैक्सीन को लेकर खूब चर्चा हो रही है और इसके टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं।

क्या है ये एचपीवी वैक्सीन और इससे किस प्रकार का लाभ हो सकता है?

एचपीवी वैक्सीन, ह्यूमन पेपिलोमावायरस के कारण होने वाले संक्रमण को रोकने में मददगार है। एचपीवी टीकों को महिलाओं में होने वाले जानलेवा सर्वाइकल कैंसर से बचाव का सबसे कारगर तरीका माना जाता है।

सर्वाइकल कैंसर से बचाती है वैक्सीन

सर्वाइकल कैंसर, सर्विक्स में कोशिक. ाओं की अनियंत्रित वृद्धि के कारण होता है। सर्विक्स गर्भाशय का निचला हिस्सा होता है जो योनि से जुड़ता है। ह्यूमन पेपिलोमावायरस के विभिन्न प्रकार, जिन्हें एचपीवी भी कहा जाता है, वे सर्वाइकल कैंसर पैदा करने वाले प्रमुख कारक हैं।

एचपीवी, यौन संपर्क से फैलता है। इस प्रकार के संक्रमण और इसकी जटिलताओं को दूर करने के लिए एचपीवी वैक्सीन को कारगर पाया गया है।

सर्वाइकल कैंसर, महिलाओं में मृत्यु दर के प्रमुख कारणों में से एक है। भारतीय महिलाओं में होने वाले सभी कैंसर में लगभग 6–प्रतिशत मामले सर्वाइकल कैंसर के होते हैं। सीडीसी (रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र) 12 वर्ष की आयु में नियमित एचपीवी टीकाकरण का सुझाव देता है। ये टीका सिर्फ सर्वाइकल कैंसर ही नहीं, कई और गंभीर प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं से बचाने में भी कारगर हो सकता है।

तमाम प्रकार के कैंसर से भी मिल सकती है सुरक्षा

स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, सर्वाइकल कैंसर के अलावा, एचपीवी टीकाकरण से गुदा, लिंग और ऑरोफरीन्जियल कैंसर के खतरे को कम करने में भी मदद मिल सकती है।

इन कैंसर के कारण हर साल लाखों लोगों की मौत हो जाती है।

समय पर लक्षणों की पहचान और इलाज न होने के कारण इन कैंसर का मृत्युदर अधिक देखा जाता रहा है।

अगर समय पर एचपीवी टीकाकरण करा लिया जाए तो इस प्रकार के कई कैंसर के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है।

एचपीवी के खिलाफ हर्ड इम्युनिटी के लिए टीकारकण जरूरी

एचपीवी वैक्सीन, न केवल टीकाकरण करा चुके व्यक्ति की रक्षा करती है साथ ही समुदायों के भीतर वायरस के संचरण को कम करने में भी मददगार है।

इस अवधारणा को हर्ड इम्युनिटी कहा जाता है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, आबादी में किसी भी प्रकार के संक्रमण की गति को कम करने के लिए हर्ड इम्युनिटी से लाभ मिल सकता है, जिसमें अधि. कतर लोग संक्रमण से सुरक्षित हों और उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता विक. सित हो चुकी हो।

टीकाकरण के लिए डॉक्टर से लें सलाह

स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, सर्वाइकल कैंसर बड़ा जोखिम बनकर उभरता देखा जा रहा है।

जब आबादी के एक बड़े हिस्से को एचपीवी के खिलाफ टीका लगता है, तो इससे उन लोगों को भी लाभ मिल सकता है जिन्हें चिकित्सा कारणों या उम्र के कारण टीका नहीं लगाया जा सकता है। यह अप्रत्यक्ष रूप से संक्रमण से सुरक्षा पाने का भी कारगर तरीका हो सकता है।

एचपीवी टीकाकरण के लिए अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें।

ब्लड शुगर लेवल बढ़ना या लो होना दोनों खतरनाक ऐसे लक्षण दिखें तो तुरंत जाएं डॉक्टर के पास

ब्लड शुगर का बढना स्वास्थ्य के लिए समस्याकारक स्थिति मानी जाती है। लंबे समय तक शुगर का लेवल बढ़े रहने से शरीर के अन्य अंगों जैसे आंखें, हार्ट, किडनी पर भी नकारात्मक असर हो सकता है। डायबिटीज के शिकार लोगों में अक्सर शुगर लेवल अधिक होने की समस्या देखी जाती है। पर क्या आप जानते हैं, शुगर बढने की तरह ही इसका लो स्तर भी आपके लिए बड़ी मुश्किलों का कारण बन सकती है। अक्सर लो शुगर लेवल के कारण कोमा होने का भी खतरा हो सकता है।

ज्यादातर लोगों में सुबह का फास्टिंग ग्लूकोज लेवल 70 से 100 मिल. ीग्राम/डीएल के बीच का स्तर सामान्य माना जाता है। वहीं भोजन के बाद 140 मिलीग्राम/डीएल या उससे कम का स्तर सामान्य शुगर लेवल है। हालांकि अगर आपका शुगर लेवल अक्सर 70 मिलीग्राम/डीएल से कम बना रहता है तो इसे लो शुगर माना जाता है। इस स्थिति को हाइपोग्लाइकेमिया कहा जाता है। ये सेहत के लिए गंभीर संकेत हो सकती है।

लो शुगर लेवल खतरनाक

स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया की समस्या अधि. कतर मधुमेह का उपचार ले रहे लोगों में देखी जाती है, पर इसका जोखिम किसी को भी हो सकता है। हाइपोग्लाइसीमिया में तत्काल उपचार की आवश्यकता होती है। समय पर इलाज न मिलने पर झटके आना, जबड़ों के सख्त होने, चेतना की हानि और कोमा का भी खतरा हो सकता है।

यही कारण है कि डायबिटीज रोगियों को नियमित अंतराल पर शुगर की जांच कराते रहने की सलाह दी जाती है।

हाइपोग्लाइसीमिया क्यों होता है?

हाइपोग्लाइसीमिया तब होता है जब आपके ब्लड शुगर (ग्लूकोज) का स्तर शारीरिक कार्यों को जारी रखने के लिए बहुत कम हो जाता है। ग्लूकोज हमारे ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। मधुमेह की दवा की अधिकता, इंसुलिन लेने के साथ शुगर कम करने वाले अन्य उपाय हाइपोग्लाइसीमिया का कारण बन सकते हैं। बिना कुछ खाए भारी मात्रा में शराब पीने से भी अचानक से शुगर का लेवल बहुत कम हो जाने की समस्या देखी जाती रही है।

यदि किसी बीमारी के कारण शरीर अधिक मात्रा में इंसुलिन का उत्पादन करने लग जाए तो इसके परिणामस्वरूप भी हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है।

कैसे पहचानें लो शुगर के लक्षण

यदि रक्त शर्करा का स्तर बहुत कम हो जाता है, तो इसके कारण कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम बढ़ जाता है। रोगी को अस्थिरता–बेचौनी, पसीना आने, अनियमित या दिल की धड़कन तेज होने, थकान, चिड़चिड़ापन, शरीर में झुनझुनी या सुन्न होने की समस्या हो सकती है। लंबे समय तक लो रहने वाले शुगर लेवल के कारण भ्रम, असामान्य व्यवहार जैसी दिक्कत, बोलने में कठिनाई, धुंधला दिखने की भी समस्या होने लगती है।

लो शुगर हो जाए तो क्या करें?

स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, यदि हाइपोग्लाइसीमिया की पहचान न हो पाए या इसे अनुपचारित छोड़ दिया जाए तो रोगी को झटके आने, कोमा यहां तक कि मौत भी हो सकती है। अगर किसी में अचानक से शुगर लेवल कम हो गया हो तो तुरंत 15 से 20 ग्राम तेजी से काम करने वाले कार्बोहाइड्रेट या मीठे बिस्किट दें। फलों का रस, सोडा, शहद या मीठी कैंडी से भी शुगर बढ़ाया जा सकता है। लक्षणों में थोड़ा आराम मिलते ही रोगी को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं।

कोरोनावायरस के शिकार लोगों में रिपोर्ट किए गए संक्रमण से मृत्यु के सबसे अधिक मामले, केस भी बढ़े

कोरोनावायरस का संक्रमण वैश्विक स्तर पर जारी है। इन दिनों कई देशों में रिपोर्ट किए जा रहे संक्रमण के मामलों के लिए ओमिक्रॉन के नए सब–वैरिएंट .1 को प्रमुख कारण माना जा रहा है। अध्ययनों में इसकी संक्रामकता दर भी काफी अधिक बताई गई है। कोरोना की इस लहर में कई देशों में मौत के मामलों में भी वृद्धि देखी गई है।

वैज्ञानिकों ने बताया वैरिएंट .1 अत्यधिक संक्रामक वैरिएंट जरूर है पर इसके कारण गंभीर रोग विक. सित होने या फिर मृत्यु का खतरा उन्हीं लोगों में अधिक हो सकता है जो पहले से ही किसी गंभीर क्रोनिक बीमारी के शिकार रहे हैं, या फिर जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी कमजोर हो।

मीडिया रिपोर्ट्स से पता चलता है कि अमेरिका, चीन, सिंगापुर सहित कई देशों में कोरोना की इस लहर के कारण मौत के मामले भी अधिक रिपोर्ट किए जा रहे हैं।

भारत में भी संक्रमितों में मृत्यु का खतरा बढ़ा है। कोरोना रोगियों में मौत के बढ़ते मामलों को समझने के लिए किए गए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने बताया कि संक्रमण से मरने वालों में सबसे अधिक मामले मधुमेह से संबंधित पाए गए हैं। महिला–युवाओं में मौत का खतरा अधिक देखा गया है।

डायबिटीज और कोविड–19

द लैंसेट डायबिटीज एंड एंडोक्रिनोलॉजी जर्नल में प्रकाशित शोध की रिपोर्ट से पता चलता है कि मधुमेह के रोगियों में कोविड–19 के कारण मौत के मामले बढ़े हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने पाया कि महामारी ने स्वास्थ्य देखभाल और जीवनशैली में व्यवधान पैदा कर दिया है, जिससे डायबिटीज रोगियों की जटिलताएं बढ़ गई हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) सहित अन्य शोधकर्ताओं की टीम ने इससे संबंधित 138 अध्ययनों की समीझा की, जिसमें पाया गया है कि महामारी के दौरान मधुमेह रोग, कोविड से मृत्यु का एक जोखिम कारक था। जिन डायबिटिक रोगियों को संक्रमण हुआ उनमें समय के साथ जटिलताएं अधिक बढ़ती हुई देखी गईं।

महामारी के दौरान बढ़े टाइप 1 डायबिटीज के केस

मौतों में वृद्धि के साथ–साथ, शोधकर्ताओं ने पाया कि आईसीयू में भी मधुमेह रोगियों की भर्ती में चौंकाने वाली वृद्धि हुई है। बच्चों और किशोरों में डायबिटिक केटोएसिडोसिस (डीकेए) के मामले भी बढ़े हैं। डीकेए मधुमेह की एक संभावित गंभीर जटिलता है, जिससे शरीर में विषाक्तता बढने, उल्टी–पेट दर्द, पेशाब से संबंधित समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है।

शोधकर्ताओं ने बताया कि महामारी के दौरान टाइप–1 डायबिटीड के भी उम्मीद से अधिक नए मामले सामने आए हैं।

इस प्रकार के मधुमेह वाले लोग महामारी के दौरान अधिक बीमार भी हुए। टाइप–2 डायबिटीज की तुलना टाइप 1 डायबिटीज के केस कम देखे जाते रहे हैं। ये एक ऑटोइम्यून बीमारी है जिसका आमतौर पर बचपन में निदान किया जाता है।

क्या कहती हैं शोधकर्ता?

अध्ययन की प्रमुख शोधकर्ताओं में से एक हार्टमैन–बॉयस कहती हैं, महामारी के दौरान किए गए अधि. कतर शोध में पाया गया कि क्रोनिक बीमारियों के शिकार लोगों में संक्रमण से गंभीर जटिलताओं और मृत्यु का खतरा अधिक हो सकता है।

हम इस बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या अन्य किसी महामारी का भी इन रोगियों पर गंभीर असर हो सकता है?

फिलहाल जैसे हल्के स्तर वाले वैरिएंट से भी बचाव को लेकर डायबिटीज के शिकार लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी जाती है।

डायबिटीज रोगी करें बचाव

स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, डायबिटीज की स्थिति शरीर को अंदर ही अंदर कमजोर करती जाती है, इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर भी नकारात्मक असर हो सकता है।

यही कारण है कि मधुमेह के शिक. ार लोगों में कोरोना से मौत का खतरा अधिक देखा जा रहा है।

इन दिनों बढ़ रहे कोरोनावायरस से भी क्रोनिक बीमारी वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतते रहने की आवश्यकता है।

क्योंकि इस वायरस का शरीर पर गंभीर असर होने का खतरा हो सकता है।

देश को 2027 तक कुष्ठ रोग मुक्त बनाने का लक्ष्य, पर कई राज्यों में अब भी रोग में वृद्धि जारी

कुष्ठ रोग वैश्विक स्तर पर दशकों से स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बड़ी चिंता का कारण रहा है। लोगों में जागरूकता और रोग के बारे में सही जानकारी के अभाव के चलते कुष्ठ रोग को लेकर बने सामाजिक कलंक के भाव ने इसे और चुनौतीपूर्ण बना दिया था। हालांकि एक–दो दशक में इस रोग में कमी दर्ज की गई है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा समय में कुष्ठ रोग के सबसे ज्यादा मामले अफ्रीकी और एशियाई देशों में देखे जा रहे हैं। कुष्ठ रोग के बारे में लोगों को जागरूक और शिक्षित करने के उद्देश्य से हर साल जनवरी महीने के आखिरी रविवार को विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है।

हालिया रिपोर्ट्स में भारत में कुष्ठ रोग के मामले बढने को लेकर अलर्ट किया गया है। महाराष्ट्र में 18 साल से कम उम्र के बच्चों में कुष्ठ रोग के मामलों की बढ़ती संख्या ने स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता बढ़ा दी है। पिछले साल अप्रैल से दिसंबर के बीच रिपोर्ट किए गए कुष्ठ रोग के 17,048 नए मामलों में से 1,160 मामले (यानी सात प्रतिशत) बच्चों में देखे गए हैं। अधिक. ारियों ने कहा, बच्चों में कुष्ठ रोग का बढना एक संवेदनशील संकेतक है।

अमेरिका के कई राज्यों में भी बढ़े मामले अंतराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स से पता चलता है कि अमेरिका में भी पिछले कुछ वर्षों में कुष्ठ रोग के नए मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। वर्ष 2000 के बाद से अमेरिका के दक्षिणी हिस्सों में कुष्ठ रोग के नए मामलों की दर बढ़ी है। अमेरिका के कुष्ठ रोग का लगभग हर पांचवा केस सेंट्रल लोरिडा से है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, कुष्ठ रोग अपने साथ कई और चुनौतियां भी लेकर आता है, जिसमें सामाजिक कलंक का भाव सबसे ज्यादा देखा जाता रहा है।

नोट- आप का सामना की हेल्थ,युवा सामना कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से पेशेवर पत्रकारों द्वारा बातचीत के आधार पर पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किये जाते है। आप का सामना लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।

संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है बल्कि यह जीवन जीने का एक माध्यम है।

-डॉ० भीमराव अंबेडकर

संपादकीय

जरूरत डॉ. आंबेडकर के मूल्यों को अपनाने की

दिसंबर का महीना वैसे तो बाबा साहब आंबेडकर को श्रद्धांजलि देने का महीना होता है, लेकिन पिछले महीने सर्वोच्च न्यायालय ने वकीली–मुद्रा में उनकी सात फुट की प्रतिमा स्थापित कर उन्हें पूर्वज अधिवक्ता के रूप में विशेष रूप से याद किया।

स्मरणीय तो आंबेडकर का शोध प्रॉब्लम ऑफ रुपी भी है, जिसे उन्होंने सौ–साल पूर्व लंदन के स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स में पेश किया था और जिस पर उन्हें डॉक्टरेट ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त हुई थी। रिजर्व बैंक की स्थापना का आधार यही थीसिस है, जिसे अमर्त्य सेन ने नोबेल पुरस्कार के योग्य शोध माना।

सौ साल पहले 1923 में डॉ. आंबेडकर ने लंदन से पढ़ाई पूरी कर वकालत करने के उद्देश्य से बॉम्बे हाईकोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की थी। वहां उन्होंने कई ऐतिहासिक मुकदमे लड़े और जीते। वह जानते थे कि निचली अदालतों में सामान्य भारतीय के लिए न्याय मिल पाना कठिन है, इसलिए ब्रिटिश सरकार के 2,500 रुपये मासिक पर वकालत का प्रस्ताव ठुकरा कर उन्होंने ठाणे, नाग. पुर और औरंगाबाद की जिला अदालतों में वकालत की। तब सर्वाधिक वंचित भारतीयों के बीच से पहला न्यायप्रिय अधिवक्ता खड़ा हुआ था।

कदाचित इसी कृतज्ञता बोध के मद्देनजर सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने उन्हें श्फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टीट्यशन कहकर संबोधित किया। आंबेडकर के बहुआयामी ज्ञान प्रसार से ही न्यायप्रिय समाज का निर्माण होना संभव है। बीते सौ साल में विधि विषयक कई सुधार हुए हैं। नए कानूनों का निर्माण व संशोधन भी खूब हुए हैं।

लेकिन अधिवक्ता आंबेडकर का सम्मान तो तभी पूर्ण होगा, जब न्यायालयों में जजों की नियुक्ति प्रक्रिया अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को लेकर समावेशी और विविधतापूर्ण हो। संविधान लागू होने के करीब साढ़े सात दशक. ों की यात्रा के बाद भी लोकतांत्रिक न्याय पर राजशाही प्रथाओं, परंपराओं और पूर्वाग्रहों का दबाव है। दलितों, आदिवासियों और अन्य निर्धन तबकों के लिए वकीलों की फीस दे पाना मुश्किल है, इस कारण वे मामूली अपराधों या झूठे मुकदमों में लंबी सजाएं काटते हैं और उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो पाती। सरकारी वकीलों तथा जजों के अभाव में न्यायालयों में फाइलों के अंबार लगे रहते हैं।

पराधीन भारत में जिस अस्पृश्य–बहिष्कृत समाज से एक बेजोड़ वकील आया, स्वतंत्र भारत के न्यायालयों में उस समाज के जज कम हैं, जो समाज की संवेदनशीलता के भुक्तभोगी अनुभवों की रोशनी में न्याय प्रक्रिया को सार्थकता प्रदान करने के लिए आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि देश की संसद ने इस स्थिति को कभी गंभीरता से लिया ही न हो। पूर्व राष्ट्रपति डॉ. केआर नारायण ने तो जजों की नियुक्तियों की फाइल पर ही टिप्पणी की थी कि इस सूची में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के जजों के नाम शामिल नहीं हैं, जबकि वे देश की बहुत बड़ी आबादी हैं।

पिछले साल भी यह मुद्दा मीडिया में उठा था और कहा गया था कि न्यायधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया समावेशी और विविधतापूर्ण नहीं बन पाई है। आज अंग्रेजों के जमाने की आपराधिक संहिता खत्म कर नए कानूनों को मंजूरी मिल चुकी है। लेकिन पांच साल के आंकड़े ही चिंतित कर देते हैं।

शिक्षा राज्यमंत्री डॉ. सुभाष सरकार द्वारा राज्यसभा को बताए गए पांच वर्षों के आंकड़ों में 25,000 से अधिक एससी/एसटी/ओबीसी छात्रों ने आईआईटी और केंद्रीय विश्वविद्यालय छोड़ दिए। आंकड़ों के मुताबिक, इन श्रेणियों के 33 फीसदी बच्चे दसवीं के बाद ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। अनुसूचित जातियों में लड़कियां सर्वाधिक पढ़ाई छोड़ती हैं। पलायन प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च–हर स्तर पर है और ये बच्चे राजकीय शिक्षा संस्थाओं की अपेक्षा निजी संस्थाओं से अधिक बाहर हो रहे हैं।

कानूनविद डॉ. आंबेडकर मानते थे, जिस अनुपात में समाज में शिक्षा में वृद्धि होती है, उसी अनुपात में समाज की उदारता में भी वृद्धि होती है। पर मौजूदा स्थिति हताश करती है।

बेनकाब पाकिस्तान,दुनिया के सामने

बलूचिस्तान हमेशा गलत कारणों से सुर्खियों में रहता है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा, लेकिन सबसे कम आबादी वाला यह प्रांत कभी भी इस्लामाबाद या प्रधानमंत्री कार्यालय के निशाने पर नहीं रहा था। दशकों पहले यह पहली बार तब खबरों में आया, जब पाकिस्तान ने चगाई के पहाड़ों में एक परमाणु उपकरण का परीक्षण किया, जिससे इस खूबसूरत इलाके का पर्यावरण नष्ट हो गया। खनिज संपदा के मामले में यह प्रांत उम्मीद से ज्यादा समृद्ध है और तांबा एवं सोना जैसे कई खनिजों की अभी खुदाई भी नहीं हो पाई है। सुई के छोटे से इलाके में खोजी गई सुई गैस पूरे पाकिस्तान में रसोई बनाने एवं घर को गर्म रखने के लिए पाइपों द्वारा आपूर्ति की जाती है, लेकिन दुखद बात है कि बलूचिस्तान के कई इलाके इससे वंचित हैं।

इन दिनों दुनिया भर की निगाहें, मीडिया और सिटिजन जर्नलिस्टों के कैमरे इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब पर टिके हुए हैं। खुली जगहों पर हर जगह तंबू लगे हुए हैं, जिनमें बलूचिस्तान के लोग भरे हुए हैं। उनमें से अधिकांश महिलाएं, बच्चे और बूढ़ी औरतें हैं।

सुबह वे अपने प्रियजनों की तस्वीरें लेकर शांति से बैठते हैं, जिसके बारे में किसी शब्द की जरूरत नहीं है। ये युवा और बुजुर्ग उन महिलाओं और बच्चों के रिश्तेदार हैं, जिनमें से अधिकांश दशकों से लापता हैं। उनके परिजनों को कुछ पता नहीं है कि वे जीवित हैं या मृत। इन महिलाओं के लिए इससे अधिक पीड़ादायक कुछ नहीं हो सकता,है। वे मानवाधिकार उल्लंघन का भी विरोध कर रही हैं।ये बलूची नागरिक बलूचिस्तान से पैदल चलकर इस्लामाबाद पहुंचे हैं, जिन्हें वे बलूच लांग मार्च कहते हैं।

क्या भारत उठा सकता है कोई लाभ,चीन की दोहरी मुश्किलों का

ताइवान में राष्ट्रपति चुनाव से पहले, नए वर्ष के संबोधन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ताइवान को लेकर सख्त संदेश देते हुए कहा था कि ताइवान को फिर से चीन के साथ एकीकृत किया जाएगा। इससे कुछ ही दिन पहले पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के संस्थापक माओ त्से तुंग के जन्म की 130वीं वर्षगांठ के अवसर पर भी शी जिनपिंग ने दावा किया था कि चीन के साथ ताइवान का पुनः एकीकरण अपरिहार्य है। यह ताइवान में होने वाले महत्वपूर्ण चुनाव से पहले बीजिंग के दीर्घकालिक रुख पर बल देता है।

चीन 2.3 करोड़ की आबादी वाले स्व–शासित द्वीप ताइवान को अपने एक प्रांत के रूप में देखता है, जबकि ताइवान अपने संविधान और लो. कतांत्रिक ढंग से चुने गए नेताओं के साथ खुद को चीनी मुख्य भूमि से अलग मानता है। उधर ताइवान की राष्ट्रपति त्साई इंग–वेन ने अपने नए साल के संबोधन में कहा कि चीन के साथ ताइवान के संबंध ताइवान के लोगों की इच्छा से तय होने चाहिए। उनकी सरकार ने बार–बार चेतावनी दी है कि बीजिंग चुनाव में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है, जहां एक नया राष्ट्रपति और सरकार चुनी जाएगी।

असल में शी जिनपिंग का यह रुख चीन की हताशा को भी दर्शाता है, जो उसकी दोहरी चुनौतियों से उभरी है। चीन के समक्ष दो तरह की चुनौतियां हैं–आर्थिक मोर्चे पर मंदी और पश्चिमी देशों की घेरेबंदी। हाल के समय में इन चुनौतियों ने चीन के सावधानीपूर्वक निर्मित भव्य आख्यान को प्रभावी ढंग से प्रभावित किया है, जो चीनी क्षेत्र के उदय को महिमामंडित करता है। हालांकि यह मात्र प्रचार नहीं था, क्योंकि 1978 के बाद चीन में औसत वास्तविक विकास दर नौ फीसदी से ज्यादा देखी गई और कुछ चरम वर्षों में इसकी अर्थव्यवस्था 13 फीसदी के ज्यादा के दर से बढ़ी। इस सफलता ने एक गरीब कृषि संस्कृति वाले चीन को औद्योगिक दिग्गज राष्ट्र में बदल दिया। हालांकि तेजी से बदलते घटनाक्रम में चीन की अजेयता अतीत की बात लगने लगी है। कोविड–19 महामारी के प्रति इसकी शून्य सहिष्णुता और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बढ़ते तानाशाही रवैये ने चौतरफा आलोचना बटोरी है।

वर्ष 2023 के पहले तीन महीनों के मुकाबले दूसरी तिमाही में चीन की जीडीपी मात्र 0.8 फीसदी बढ़ी। चीन की अनुमानित वार्षिक विकास दर अब तीन फीसदी के करीब नजर आ रही है, जो पिछले तीन दशकों में सबसे कमजोर है। नए वर्ष की पूर्व संध्या पर जिनपिंग ने कहा कि कुछ उद्यमों (व्यवसायों) को कठिन समय का सामना करना पड़ा और कुछ लोगों को नौकरियां ढूंढने और बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मुश्किल हुई। यह शीर्ष नेतृत्व द्वारा चीनी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली विपरीत स्थितियों की दुर्लभ स्वीकारोक्ति थी।

कई अर्थशास्त्री अब मानते हैं कि चीन बहुत धीमी वृद्धि के युग में प्रवेश कर रहा है, जो प्रतिकूल जनसांख्यिकी और अमेरिका व उसके सहयोगियों के साथ बढ़ते विवाद के कारण और भी बदतर हो गया है और जो उसके विद. शी निवेश तथा व्यापार को खतरे में डाल रहा है। विद्वान यह तय करने में लगे हैं कि चीन की मौजूदा आर्थिक समस्याएं अल्पकालिक हैं या संरचनात्मक। 40 खरब डॉलर के विशाल मुद्रा भंडार के साथ चीन अल्पकालिक समस्याओं से निपटने में सक्षम है। लेकिन बुजुर्ग होती आबादी, पश्चिमी बाजारों से अलगाव, स्थानीय मांग के बजाय अधिकांशतरू निवेश आधारित आर्थिक विकास जैसे संरचनात्मक मुद्दे जल्द हल होने वाले नहीं हैं।

फिर भी, चीन को जल्दबाजी में खारिज करना गलती होगा। वैश्विक उतार–चढ़ाव को देखते हुए कई लोग अब भी मानते हैं कि सभी बाधाओं के बावजूद 21वीं सदी श्चीनी सदीश होने जा रही है। दोहरे अंकों की आर्थिक वृद्धि के सुनहरे दिनों ने चीनी शासक को महत्वाकांक्षी बीआरआई परियोजना शुरू करने की प्रेरणा दी। विकास के चकित कर देने वाले रिकॉर्ड से प्रभावित होकर चीन ने श्शांतिपूर्ण विकासश की परिकल्पना से बाहर निकल कर अधिक आक्रामक रुख अपना लिया, जिससे उच्च हिमालय से लेकर दक्षिण चीन सागर तक समस्याएं पैदा हो गईं।

बीजिंग की आक्रामकता ताइवान के एकीकरण के दावे के साथ वन चाइना पॉलिसी के जबरन कार्यान्वयन में तब्दील हो गई। इसने चीन को अमे. रिका के साथ विवाद में उलझा दिया, जो ताइवान की सुरक्षा की गारंटी का दावा करता है। चीन अमेरिकी वर्चस्व वाली उदार विश्व व्यवस्था को चुनौती देने के लिए तैयार है। उसने पश्चिम की रणनीतिक घेरेबंदी को तोडने के लिए रूस से हाथ मिलाया है। चीन की बढ़ती ताकत को संतुलित करने के लिए अमेरिका ने कई देशों को चीन–केंद्रित विश्व व्यवस्था की याद दिलाई है, जिसने कभी कोरिया और वियतनाम जैसे देशों को अर्ध संप्रभु स्थिति में रखा था। चीन की मौजूदा आक्रामकता को अतीत के गलत कार्यों के आलोक में देखने से हमें इस एशियाई दिग्गज की भावी कार्रवाई के संकेत मिलते हैं।

चीन में व्याप्त मौजूदा उथल–पुथल से भारत लाभ उठाने की स्थिति में है। चीन की दोहरी चुनौती के विपरीत भारत नई आर्थिक उड़ान के साथ–साथ पश्चिम द्वारा हिंद–प्रशांत क्षेत्र में प्रमुख खिलाड़ी की मान्यता पाने के संकेत देख रहा है। क्वाड का संस्थापक सदस्य होने के नाते भारत न केवल रूस से संबंध बनाए रखकर, बल्कि वाशिंग्टन की दबाव की रणनीति के खिलाफ रूस से सस्ता तेल खरीदकर अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर रहा है। जब चीन को अजेय चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, तब भारत बढ़त हासिल करता दिख रहा है। दुनिया ने लोकतंत्र, जनसांख्यिकी और पूंजीवाद जैसे क्षेत्रों में चीन पर भारत की बढ़त पहचानी है। पश्चिम का मानना है कि स्थायी शक्ति संतुलन के लिए चीन के खिलाफ भारत को खड़ा करने की जरूरत है, जिसने भारत को इस क्षेत्र में एक अपरिहार्य शक्ति बना दिया है। चीन के आक्रामक रवैये ने अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में भारत को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है, जिसका उपयोग तेजी से और दृढ़ संकल्प के साथ किया जाना चाहिए। जनसांख्यिकी भारत के पक्ष में है, लेकिन बेरोजगार युवाओं की फौज को नियोजित करने के लिए गंभीर कोशिश करनी होगी। चीन का मुकाबला करने के लिए चीन से सीखना होगा। देश की बड़ी और युवा आबादी का लाभ उठाकर हम विनिर्माण के क्षेत्र में चीन की जगह ले सकते हैं।

आर्थिक वृद्धि के लाभ से वंचित है बड़ी आबादी

इस देश के अलग–अलग हिस्सों को मिलाकर लगभग 142 करोड़ लोग रहते हैं और मेरी चिंता यह है कि इनमें से कितने लोग सुखी हैं और कितने लोग सुखी नहीं हैं। पिछले दिनों मैंने कई लेख पढ़े, जो सरकार के इस दावे को मजबूती प्रदान करती थी कि हर आदमी खुश है। उन लेखकों का दावा है कि लोग खुश इसलिए हैं, क्योंकि देश में अभूतपूर्व आर्थिक विकास हुआ है, जिसका लाभ हर क्षेत्र के लोगों को मिल रहा है। मैं यह नहीं कहता कि आर्थिक वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन निश्चित तौर पर यह वृद्धि अभूतपूर्व नहीं है।

आर्थिक वृद्धि का सुनहरा दौर तो पूर्ववर्ती यूपीए सरकार में 2005 से 2008 की तीन वर्षों की वह अवधि में था, जब अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्रमशरू 9.5, 9.6 और 9.3 फीसदी सालाना थी। जबकि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री काल के पिछले नौ वर्षों में औसत वृद्धि दर 5.7 प्रतिशत रही है। अगर मौजूदा वित्त वर्ष में 6.5 फीसदी की अनुमानित वृद्धि दर को भी इसमें जोड़ लें, तो औसत वृद्धि दर 5.8 प्रतिशत होगी। यह वृद्धि दर न तो अभूतपूर्व है और न ही शानदार। यह संतोषजनक वृद्धि दर है, लेकिन न तो सुदूरप्रसारी है और न ही पर्याप्त।

सरकार की आर्थिक नीति प्रत्यक्ष करों को कम रखने, अप्रत्यक्ष करों को ज्यादा व दबाव भरा बनाए रखने तथा वर्चस्ववादी उपायों का मिला–जुला स्वरूप है। सडक़, रेलवे, बंदरगाह और हवाई अड्डे जैसे ढांचागत क्षेत्रों में पूंजी निवेश ज्यादा है, जबकि शिक्षा व स्वास्थ्य सेवा में आवंटन कम है, और महिला विकास जैसे कुछ क्षेत्रों में सब्सिडी की सुविधा है। ऐसे में, संतोषजनक वृद्धि दर ने समाज के कुछ क्षेत्रों को खुश किया है। इस तस्वीर का स्याह पक्ष यह है कि इसमें कई क्षेत्रों के लोग पीछे छूट गए हैं–कुछ क्षेत्रों के लोग तो गिनती में ही नहीं हैं–और ऐसे तमाम क्षेत्रों को मिला दिया जाए, तो यह बहुत बड़ी आबादी है। इनमें वे 82 करोड़ भारतीय हैं, जिन्हें हर महीने प्रति व्यक्ति पांच किलोग्राम मुत राशन मिलता है।

मुत राशन योजना कोई गर्व की चीज नहीं है, जिससे देश की आर्थिक उन्नति या समृद्धि मापी जा सके। देश के आधे परिवार चावल या गेहूं खरीद सकने में समर्थ क्यों नहीं हैं? इसका जवाब है कम आय या बेरोजगारी।

देश में एक और बड़ी आबादी खुश नहीं है। ये वे लोग हैं, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है।

सरकार अब रोजगार सृजन की बात नहीं करती। उसका मानना है कि स्व रोजगार में हो रही वृद्धि की बात कहकर वह लोगों को भुलावा दे सकती है। नाखुश लोगों का एक और वर्ग है। ये लोग मुद्रास्फीति के मारे हुए हैं। इस श्रेणी में शीर्ष के उन 10 फीसदी लोगों को छोडक़र, जिनके पास देश की कुल संपत्ति का 60 फीसदी है और जो राष्ट्रीय आय का 57 प्रतिशत कमाते हैं, देश की पूरी आबादी है।

चंडीगढ़ नगर निगम का बजट वर्ष 2024&25 के लिए 2325-21 करोड़ रुपये का

pMhx<A मेयर कुलदीप कुमार ने बुधवार को वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए नगर निगम का 2325.21 करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जिसे सदन ने पास कर दिया। बजट में स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ शिक्षा एवं सामुदायिक केंद्रों के निर्माण पर काफी फोकस किया गया है। गांवों के विकास और आवारा कुत्तों की समस्या के समाधान के लिए बजट को बढ़ाया गया है। इसके अलावा शहर में मजबूत शिकायत निवारण प्रणाली के लिए श्श्मेयर आप के द्वार पेश्श अभियान शुरू करने की भी घोषणा की गई है। साथ ही मेयर ने घोषणा की कि इस साल जून तक डड्डूमाजरा से कूड़े के पहाड़ को साफ कर दिया जाएगा।बजट बैठक में भाजपा पार्षदों के अलावा मनोनीत पार्षद शामिल नहीं हुए इसलिए आप और कांग्रेस के सभी पार्षदों ने ही बजट को लेकर कुछ सुझाव दिए और मेयर कुलदीप कुमार का धन्यवाद किया। पार्षद गुरप्रीत सिंह गाबी ने कहा कि निगम में 11 हजार कर्मचारी हैं लेकिन उनके कल्याण के लिए 90 लाख रुपये ही रखे गए हैं। इससे उनका कुछ नहीं होगा इसलिए इसे बढ़ाया जाना चाहिए। जसबीर सिंह लाडी ने कहा कि दो सालों में गांवों का विकास नहीं हुआ है। उस पर ध्यान देना चाहिए। लाल डोरे के बाहर लोगों को सुविधा मिले और गांवों के युवाओं को नौकरी में प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

पार्षद रामचंदर यादव ने कहा कि उनका वार्ड सबसे बड़ा है लेकिन वहां सीवरेज की काफी समस्या है। पार्षद सचिव गालव ने पीजीआई के बाहर गर्मी में भी रैन बसेरों की व्यवस्था करने की मांग की ताकि लोगों को राहत मिल सके। पार्षद तरुणा मेहता ने अपने वार्ड के सरकारी मकानों की खस्ताहाल को लेकर कहा कि उनके लिए अलग बजट रखना चाहिए। मेयर ने कहा कि इन सभी सुझावों पर विचार किया जाएगा।

प्रशासन से मिले 560 करोड़, खुद की कमाई 530 करोड़, बाकी डीएफसी के भरोसे नगर निगम ने वर्ष 2024–25 के लिए 2325.21 करोड़ रुपये का बजट पास किया है। निगम को प्रशासन से 560 करोड़ रुपये मिलेंगे जबकि संपत्ति कर, पानी का बिल, गारबेज शुल्क, पार्किंग, पेट्रोल पंप, इलेक्ट्रिसिटी सेस व अन्य से निगम का अनुमान है कि उन्हें 530 करोड़ रुपये की कमाई होगी। इसके अलावा नगर निगम ने दिल्ली फाइनेंस कमीशन (डीएफसी) की चौथी सिफारिश के अनुसार 1651 करोड़ रुपये की ग्रांट इन एड प्रशासन से मांगी है। निगम के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि रिवाइज्ड एस्टीमेट में उन्हें यह पैसे मिल जाएंगे, जिससे कि उन्हें जितने पैसे कम पड़ रहे हैं वो पूरे हो जाएंगे।

वेंडरों का बजट 10.10 करोड़ से बढ़ाकर 17.10 करोड़ किया

मेयर आप के द्वार पे अभियान के तहत नगर निगम और प्रशासनिक अधिकारी हर वार्ड में लोगों की समस्याएं सुनेंगे और उनका समाधान करने का हरसंभव प्रयास करेंगे। बजट में शहर में वेंडरों (छोटी दुकान चलाने वाले) के लिए 17.10 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है, जो पिछले साल 10.10 करोड़ रुपये था। ईडब्ल्यूएस कॉलोनियों के रखरखाव और समस्या निवारण के लिए इस वर्ष 6.00 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है जो पिछले साल 2 करोड़ 88 लाख रुपये था। बजट के दौरान मेयर कुलदीप कुमार ने घोषणा की कि हम चंडीगढ़ प्रशासन से बात कर ईडब्ल्यूएस कॉलोनियों को नगर निगम के अधीन लाएंगे।

स्वास्थ्य और लाइब्रेरी खोलने पर फोकस

स्वास्थ्य ढांचे को और मजबूत करने की जरूरत को देखते हुए पिछले साल के 10 लाख रुपये की तुलना में इस वर्ष 2.00 करोड़ रुपये के बजट की व्यवस्था की गई है। इसके तहत दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर शहर में चंडीगढ़ क्लीनिक खोले जाएंगे। शहर में शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए सभी सामुदायिक केंद्रों में पुस्तकालय स्थापित करने के लिए 1.00 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। सामुदायिक केंद्रों के बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने और नए सामुदायिक केंद्रों के निर्माण के लिए 7.15 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

जून से मनीमाजरा वासियों को 24 घंटे पानी, लाल डोरे के बाहर कनेक्शन देने की घोषणा

शहर के अंदर 154 किलोमीटर लंबी टीटी वाटर पाइप लाइन बिछाने के लिए 72.00 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इसके जरिए 1900 से ज्यादा गार्डनों, पार्कों और ग्रीन बेल्ट तक टीटी पानी पहुंचाया जाएगा। इस साल चंडीगढ़ के इतिहास में पहली बार लोगों को 24 घंटे पीने का पानी मिलेगा। मनीमाजरा वासियों को इस साल जून से 24 घंटे पानी मिलेगा। इसके अलावा धनास, खुड्डा अलीशेर, खुड्डा लाहौरा, खुड्डा जस्सू, कैंबवाला, रायपुर कलां और सारंगपुर में पानी की आपूर्ति की जाएगी। बजट के दौरान मेयर कुलदीप कुमार ने इस साल लाल डोरे के बाहर के सभी घरों में पानी का कनेक्शन देने की भी घोषणा की।

आवारा कुत्तों की समस्या का समाधान करने के लिए बढ़ाया बजट

शहर में आवारा कुत्तों के कारण शहरवासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए पूरे बाय लॉज को लागू करने की घोषणा बजट में की गई है। पिछले साल इसके लिए 50 लाख रुपये का बजट रखा गया था, जिसे इस बार बढ़ाकर 2.00 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसके तहत और अधिक एबीसी सेंटर खोले जाएंगे और आवारा कुत्तों का प्रबंधन किया जाएगा। नसबंदी कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे और टीकाकरण की भी व्यवस्था की जाएगी।

नए मंत्रिमंडल में शामिल किए 16 नए मंत्री प्रचंड ने, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने दिलाई शपथ

dkBekMA नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने बुधवार को अपने मंत्रिमंडल में 16 नए मंत्रियों को शामिल किया। पूर्व गुरिल्ला नेता प्रचंड ने हाल ही में नेपाली कांग्रेस का साथ छोड़कर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकी.त मार्क्सवादी–लेनिनवादी) के साथ नया गठबंधन बनाया, जिसके बाद तीन मंत्रियों ने पद की शपथ ली थी।

प्रचंड ने नेकपा (माओवादी केंद्र) से चार, नेकपा (एकी.त माओवादी लेनि. नवादी) से सात, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) से तीन और नेकपा (एकी. त सोशलिस्ट) से दो को मंत्री बनाया। राष्ट्रपति कार्यालय के मुताबिक, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास में एक समारोह में नवनियुक्त मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (यूएमएल)
रघुवीर महासेठ, उप प्रधान मंत्री और भौतिक संरचना मंत्री
पदम गिरी, विधि न्याय एवं संसदीय कार्य मंत्री
हरि उप्रेती रक्षा मंत्री
भगवती चौधरी, महिला वालवालिका मंत्री
राजेन्द्र राय, जल मंत्री
दामोदर भंडारी, उद्योग मंत्री
ज्वालाकुमारी साह, कृषि मंत्री
बलराम अधिकारी, भूमि प्रबंधन मंत्री
माओवादी केन्द्र
नारायणकाजी श्रेष्ठ, उप प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री
वर्षमान पुन, अर्थ मंत्री
शक्ति बस्नेत, ऊर्जा मंत्री
रेखा शर्मा, संचार मंत्री
हित बहादुर तामांग
राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी
रवि लामिछाने, उप प्रधान मंत्री

सोमवार को नियुक्त किए गए तीनों मंत्रियों को बुधवार को विभाग आवंटित किए गए। सोमवार को नया गठबंधन बनने के बाद चार राजनीतिक दल एक आठ सूत्रीय समझौते पर पहुंचे। चारों दलों के पास 142 सीट की साझा ताकत है, जो साधारण बहुमत साबित करने के लिए पर्याप्त है। गठबधंन में बदलाव के लिए प्रधानमंत्री को तीस दिनों के भीतर संसद में विश्वास मत हासिल करना होता है। प्रचंड 25 दिसंबर 2022 को नेपाली कांग्रेस के समर्थन से तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बने थे। उनकी नेकपा (माओवादी केंद्र) प्रतिनिधि सभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। प्रति. निधि सभा में सबसे बड़ी पार्टी नेपाली कांग्रेस से गठबंधन तोडने़ के बाद प्रचंड ने ओली से हाथ मिला लिया, जिन्हें प्रचंड का सबसे बड़ा आलोचक माना जाता था।

पिछले साल नेकपा (एकी.त मार्क्सवादी लेनिनवादी) ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए मुख्य विपक्षी दल के उम्मीदवार का समर्थन करने को लेकर विवाद के बाद प्रचंड सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। नेकपा (एकी.त मार्क्सवादी लेनिनवादी) को 78 सीट मिली, जबकि माओवादी केंद्र को 32 सीट मिली हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी और नेकपा (एकी.त समाजवादी) ने क्रमशः 20, 14, 12 और 10 सीट जीतीं। 2017 के चुनाव में प्रचंड और ओली ने अपनी पार्टियों का विलय कर लिया और आसानी से बहुमत हासिल किया।

बाइडन को बहस की चुनौती दी ट्रंप ने

o,f'kxVuA 5 मार्च को हुए प्राइमरी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन ने लगभग क्लीन स्वीप करते हुए जीत दर्ज की। रिपब्लिकन पार्टी में ट्रंप को चुनौती दे रहीं एकमात्र उम्मीदवार निक्की हेली ने भी बुधवार को सुपर ट्यूसडे के नतीजे जारी होने के बाद अपनी उम्मीदवारी वापस लेने का एलान कर दिया। जिसके बाद नवंबर में अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव में जो बाइडन का मुकाबला डोनाल्ड ट्रंप से होना लगभग तय हो चुका है।

डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडन को दी चुनौती

जो बाइडन से मुकाबला तय होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भी बाइडन को डिबेट की चुनौती दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर साझा किए एक पोस्ट में लिखा कि श्यह हमारे देश और लोगों के लिए अच्छा रहेगा कि अगर जो बाइडन और मैं अमेरिका के लिए अहम मुद्दों पर बहस करें। मैं कहीं भी, कभी भी डिबेट के लिए तैयार हूं।श डोनाल्ड ट्रंप भले ही जो बाइडन को बहस की चुनौती दे रहे हैं, लेकिन वह खुद अभी तक रिपब्लिकन पार्टी की किसी डिबेट में शामिल नहीं हुए। निक्की हेली ने कई बार ट्रंप को बहस की चुनौती दी थी, लेकिन ट्रंप ऐसी किसी बहस में शामिल नहीं हुए। अमेरिका में इस साल नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव एक तरह से 2020 में हुए चुनाव की पुनरावृत्ति दिख रहे हैं, जिसमें भी जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप का मुक. ाबला हुआ था और एक करीबी मुक. ाबले में जो बाइडन ने ट्रंप को पटखनी दे दी थी।

ये मुद्दे तय करेंगे चुनाव के नतीजे

अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जो मुद्दे अहम रहने वाले में हैं, उनमें अर्थव्यवस्था, अवैध प्रवासी, विदेश नीति, जलवायु परिवर्तन और लोकतंत्र प्रमुख हैं। खासकर डोनाल्ड ट्रंप का जोर अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर रहेगा। हाल ही में ट्रंप ने अमेरिका–मेक्सिको बॉर्डर का दौरा भी किया था, जहां से बड़ी संख्या में अमेरिका में अवैध प्रवासी प्रवेश करते हैं। ट्रंप कई बार अपनी जनसभाओं में बाइडन सरकार को अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर घेर चुके हैं। बाइडन के कार्यकाल में अमे. रिका कोविड संकट से बाहर आया। बेरोजगारी दर कम है और स्टॉक भी उच्च स्तर पर हैं। हालांकि अहम बात ये है कि क्या अमेरिका के लोग मानते हैं कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में है। सर्वे से तो पता लगता है कि अर्थव्यवस्था के मामले में अमे. रिकी लोग ट्रंप के कार्यकाल को ज्यादा महत्व दे रहे हैं।

अफगानिस्तान से जिस तरह से अमे. रिकी सेना निकली, ये कुछ विदेश नीति के मुद्दे हैं, जिन पर ट्रंप, बाइडन सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। अमेरिकी चुनाव में जलवायु परिवर्तन भी बड़ा मुद्दा है, लेकिन यहां बाइडन, ट्रंप पर भारी पड़ते नजर आते हैं क्योंकि ट्रंप तो जलवायु परिवर्तन को मानते ही नहीं हैं।

चार बार मुख्यमंत्री रहे करुणाकरण की बेटी पदमजा वेणुगोपाल ने थामा भाजपा का दामन,कांग्रेस को बड़ा झटका

ub fnYyhA केरल के पूर्व मुख्यमंत्री के करुणाकरण की बेटी भाजपा में शामिल हो गई हैं। कांग्रेस नेता पद्मजा वेणुगोपाल कद्दावर कांग्रेसी पिता की विरासत छोड़कर भाजपा का दामन थामा है। गुरुवार शाम दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पद्मजा को पार्टी की सदस्यता दिलाई। सदस्यता ग्रहण करने के बाद पद्मजा ने कहा कि अपने सियासी करियर में वे पहली बार राजनीतिक दल बदल रही हैं। उन्होंने कहा कि वे लंबे समय से कांग्रेस की कार्यशैली से नाखुश थीं। उन्होंने कहा कि भाजपा का दामन उन्होंने बिना किसी शर्त के थामा है। कांग्रेस नेताओं ने उनके फोन उठाना बंद कर दिए थे।

सोनिया गांधी का बहुत सम्मान, लेकिन उन्होंने कभी समय नहीं दिया

पद्मजा वेणुगोपाल का आरोप है कि कांग्रेस आलाकमान तक अपनी पीड़ा और शिकायत पहुंचाने के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि वे केरल से दिल्ली कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मिलने आईं, लेकिन उन्होंने भाव नहीं दिया। किसी ने मिलने की जहमत नहीं उठाई। बकौल पद्मजा, मैं सोनिया गांधी का बहुत सम्मान करती हूं लेकिन उन्होंने मुझे कभी समय नहीं दिया।

रिपोर्ट्स के मुताबिक पद्मजा कांग्रेस उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुकी हैं। हाल ही में पार्टी ने उन्हें महासचिव पद पर नियुक्त किया था।

दक्षिण भारत पर है भाजपा का फोकस

चार बार मुख्यमंत्री रहे करुणाकरण की बेटी पद्मजा का भाजपा सदस्य बनना इस दृष्टिकोण से भी अहम है, क्योंकि भाजपा अपना जनाधार मजबूत करने के लिए दक्षिण भारत समेत ऐसे इलाकों पर फोकस कर रही है, जहां अभी पार्टी के पास पर्याप्त वोट और सांसद–विधायक नहीं हैं। केरल भी उन राज्यों में शामिल है, जहां भाजपा को अभी सत्ता पर असर डालने के नजरिए से शून्य से शुरुआत करनी है।

कांग्रेस से नाराजगी का कारण

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि पद्मजा विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद से नाराज चल रही थीं। सूत्रों के मुताबिक सियासी मात के बाद पद्मजा राज्यसभा नामांकन पाने की उम्मीद कर रही थीं, लेकिन पार्टी ने विचार नहीं किया।

उन्हें लोकसभा चुनाव 2024 में भी टिकट मिलने की संभावना न के बराबर थी।

खबरों के मुताबिक कांग्रेस ने सभी मौजूदा सांसदों को मैदान में उतारने का फैसला किया है।

स्वामी,सम्पादक,प्रकाशक व मुद्रकः संतोष कुमार शुष्टा, आकाश व्यू, छकड़ायल रोड, कमला नगर, संजौली शिमला हि0 प्र0 – 171006 से प्रकाशित तथा सिग्मा प्रिंटर बलॉक न.6,शॉप न.170 एसडीए कॉम्पलेक्स कसुम्पटी शिमला से मुद्रित। किसी भी वाद विवाद का न्याय क्षेत्र शिमला ही मान्य होगा। मोबाईलः 09418453928,9805192400 e-mail: aapkasaamna@gmail.com